तिब्बत देश

हान दादागीरी और तिब्बत का सवाल

दलाई लामा आज की दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में हैं जो हिंसा के बजाए अहिंसा में, टकराव के बजाए बातचीत में और घृणा के बजाए करुणा में विश्वास करते हैं। इसलिए देखने सुनने वालों को इस बात पर हैरानी होती है कि चीनी नेताओं और आधिकारिक प्रवक्ताओं की ओर से अपने लिए 'गद्दार', 'प्रतिक्रियावादी भगोड़ों का सरदार', 'डकैतों का सरगना', 'प्रगति के रास्ते की चट्टान', और 'विभाजनवादी' जैसे अपशब्द सुनने के बाद भी दलाई लामा ने कभी चीनी नेताओं के लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि दुनिया की कड़वाहट भरी राजनीति को रोज़–रोज़ देखने वालों को यह देखकर अजीब लगता है कि चीन सरकार और चीनी नेताओं की किसी बात की आलोचना करने से पहले दलाई लामा उनके किसी न किसी गुण की प्रशंसा भी जरूर करते हैं।

उदाहरण के लिए तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ 1959 की तिब्बती जनक्रांति की 48वीं सालगिरह के मौके पर अपने वार्षिक संदेश में इस बार दलाई लामा ने चीनी राष्ट्रपति हू जिन–ताओ के इस विचार की प्रशंसा की है कि एक समरसता पूर्ण समाज बनाना जरूरी है। यह प्रशंसा करने के बाद ही उन्होंने चीनी नेता को यह याद दिलाया है कि चीन में गैर हान जातियों और तिब्बत जैसी अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं को न तो बराबरी का दर्जा मिला है और न उन्हें वे आजादियां हैं जो खुद चीन के संविधान में शामिल हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को याद दिलाया है कि जिस सामाजिक समरसता की वह बात करते हैं वैसे समाज के निर्माण का आधार है लोगों में पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देना। और ऐसा तभी हो सकता है जब विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, न्याय हो, समता हो। यह कहते हुए दलाई लामा ने श्री हू जिन–ताओ को याद दिलाया है कि उनके राज में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बल्कि वहां हान जाति की दादागीरी चल रही है।

दलाई लामा ने चीन सरकार को यह भी याद दिलाया है तिब्बती समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 1979 में चीनी नेता देंग सिआओ पिंग द्वारा दिए गए सुझाव को मानते हुए तिब्बत की आजादी के बजाए चीनी व्यवस्था के बीच रहकर वास्तविक स्वायत्तता का मध्यमार्ग अपनाने पर अपनी रजामंदी दिखाई है और बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। 2002 में फिर से शुरू हुए बातचीत के नए दौर में अब तक दोनों पक्षों के प्रतिनिधि पांच बार मिल चुके हैं। दलाई लामा ने चीनी नेतृत्व को बताया है कि उनके प्रतिनिधि किसी भी समय इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन उनकी शालीनता का हाल यह है कि उन्होंने इस बात का ज़िक्र तक नहीं किया कि चीन ने इस बातचीत को दलाई लामा के सभी आग्रहों के बावजूद पिछले एक साल से वहीं का वहीं रोका हुआ है।

तिब्बत के प्रश्न का बातचीत के रास्ते हल निकाला जाए, इस बारे में दलाई लामा के अलावा उन लोगों और देशों की भी रुचि है जो पहले से हिंसा में डूबी दुनिया में एक और समस्या पर नया खून खराबा नहीं देखना चाहते। 1949–50 के दौरान तिब्बत पर हमले और जबरन कब्जे के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी सेना और चीनी प्रशासन की उपनिवेशवादी और हिंसक नीतियों की वजह से तिब्बत की 60 लाख आबादी में से 12 लाख से ज्यादा लोग पहले ही अपनी जान खो चुके हैं। तिब्बत में राजनीतिक दमन, पुलिस की हिंसा और तिब्बती नागरिकों का दम घोंटने वाली सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था की वजह से आज भी हजारों तिब्बती नागरिक अपनी जान पर खेलकर तिब्बत से बाहर भागने और विदेशों में शरण लेने पर मजबूर हो रहे हैं। इस सबके बावजूद अगर तिब्बत की नई पीढ़ी और दुनिया भर में दिन ब दिन बढ़ते उनके समर्थक हिंसा के बजाए अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीकों तक अपने आंदोलन को सीमित रखे हुए हैं तो यह उन सबके लिए तसल्ली की बात है जो इस विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने के समर्थन में हैं।

ऐसे में दलाई लामा के साथ बातचीत को साल भर से रोके रहने की चीनी नीति यह दिखाती है कि बातचीत के रास्ते तिब्बत समस्या का हल निकालने में उसकी कोई खास रुचि नहीं है। इससे पहले 1980 वाले दशक में भी बीजिंग–धर्मशाला की बातचीत हो चुकी है जिसे कुछ आगे बढ़ाकर चीनी नेता बातचीत के दरवाजे बंद कर चुके हैं। 2002 में फिर से शुरू हुए बातचीत के मौजूदा दौर के पीछे भी असली कारण चीनी इच्छा नहीं बल्कि यूरोपीय संसद का 1999 का वह प्रस्ताव था जिसमें चीन सरकार को तीन साल के भीतर बातचीत के रास्ते तिब्बत पर कोई ठोस कदम उठाने को कहा था।

तीन साल तक बातचीत को ढुलमुल गति से चलाने और फिर उसे रोक देने के इस चीनी रवैये की असलियत को समझने के लिए यह देखना जरूरी होगा कि इस बीच वह तिब्बत में चीन क्या कर रहा है? इस दौर में चीन ने तिब्बत को रेलवे से जोड़कर वहां लाखों की संख्या में चीनी नागरिकों को बसाने का अभियान पूरी गति से शुरू कर दिया है। उसके इस अभियान का लक्ष्य तिब्बती जनता को उसीके देश में एक अर्थहीन अल्पसंख्यक समूह में बदलना है। इससे पहले वह यही काम अपने मंचूरिया और भीतरी मंगोलिया जैसे उपनिवेशों में सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शुरू की गई इस बातचीत को धीरे–धीरे आगे खींचते रहने की पीछे चीनी नेताओं की एक मंशा अपने यहां 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक को भी निर्विघ्न पूरा कर लेने की है। यकीनन वे चीन को उस तरह की हालत से बचाना चाहते हैं जिसका सामना सोवियत संघ को अपने मास्को–ओलंपिक के पश्चिमी बायकॉट और उसके कारण होने वाली आर्थिक बरबादी की वजह से करना पड़ा था। बीजिंग–धर्मशाला बातचीत पर नजर रखने वाले कई विशेषज्ञों को यह आशंका है कि 2008 में ओलंपिक पूरा करने तक तिब्बत के भीतर चीनी नागरिकों की संख्या इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी होगी कि कब्जाया हुआ तिब्बत मंचूरिया और भीतरी मंगोलिया की तरह विशुद्ध चीनी हान रंग में रंग चुका होगा। उस हालत में ऐसी किसी बातचीत की न तो बीजिंग को जरूरत रहेगी और न धर्मशाला के लिए उसका कोई अर्थ रह जाएगा। ऐसे में तिब्बती विवाद लेबनान के एक नए संस्करण के रूप में सामने आ सकता है जिसके लिए शांति चाहने वाले लोग और देश शायद तैयार नहीं हैं।

–विजय क्रान्ति

10 मार्च के संदेश से पहले भारतीय सांसदों के साथ दलाई लामा – भरोसेमंद मित्र

हान जाति की दादागीरी से मुक्ति जरूरी

दलाई लामा ने बातचीत के रास्ते तिब्बती समस्या का समाधान निकालने का प्रस्ताव दोहराया

2006 वर्ष में हमें चीनी जनवादी गणतंत्र में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन नजर आए। एक ओर हमें बदनाम करने के अभियान और राजनीतिक दमन को बढ़ाया गया। दूसरी ओर स्वयं चीन में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में कुछ सुधार दिखाई दिए।

परमपावन दलाई लामा जी द्वारा 10 मार्च, 2007 के दिन तिब्बत की राष्ट्रीय जनक्रांति की 48वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिया गया वक्तव्य

1959 में ल्हासा में तिब्बती जनता की शांतिपूर्ण जनक्रांति की 48वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं उन सभी तिब्बतियों के लिए प्रार्थना करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने तिब्बती जनता के हित में यातनाएं सहीं और अपना जीवन बलिदान किया। मैं उन लोगों के साथ भी अपनी एकजुटता प्रकट करना चाहता हूं जो वर्तमान में यातनाएं और कारावास का दुख झेल रहे हैं।

2006 वर्ष में हमें चीनी जनवादी गणतंत्र में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन नजर आए। एक ओर हमें बदनाम करने के अभियान द्वारा तिब्बत में अतिवादी रुख को और अधिक कड़ा कर दिया गया और चिंतनीय रूप में राजनीतिक उत्पीड़न तथा दमन को बढ़ाया गया। दूसरी ओर स्वयं चीन में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में कुछ सुधार दिखाई दिए। विशेषकर चीनी बुद्धिजीवियों में यह धारणा बलवती हो रही है कि मात्र भौतिक प्रगति ही पर्याप्त नहीं बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित एक अर्थपूर्ण समाज का निर्माण बहुत आवश्यक है। ऐसी धारणा जोर पकड़ रही है कि वर्तमान व्यवस्था द्वारा उक्त समाज का निर्माण संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप सामान्य रूप से धर्म में विश्वास तथा विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों की इच्छा है कि मैं चीन की तीर्थ यात्रा पर आऊं और उपदेश दूं।

राष्ट्रपति हू जिन–ताओ का एक समरसता पूर्ण समाज के हित में निरंतर उद्‌बोधन प्रशंसनीय है। ऐसे समाज के निर्माण का आधार है लोगों में पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देना और ऐसा तभी हो सकता है जब विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, न्याय हो, समता हो। अतः यह बहुत जरूरी है कि प्रत्येक स्तर के अधिकारी न केवल इस ओर ध्यान दें बल्कि इन सिद्धांतों को कार्यान्वित भी करें।

जहां तक चीन के साथ संबंधों की बात है लगभग 1974 के आस पास से यह महसूस करते हुए कि किसी न किसी समय चीन के साथ वार्तालाप अनिवार्य है, हमने सभी तिब्बतियों के लिए ऐसी वास्तविक और एकीकृत स्वायत्तता प्राप्त करने की तैयारी की है जैसी चीनी संविधान में निहित है। 1979 में चीन के सर्वोच्च नेता देंग सियाओ पिंग ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता को छोड़कर तिब्बत संबंधी सभी अन्य समस्याएं बातचीत के रास्ते सुलझाई जा सकती हैं। क्योंकि यह सुझाव हमारी सोच के अनुरूप था इसलिए हमने पारस्परिक हित की मध्यमार्गीय नीति को अपनाया। तबसे आज तक 28 वर्ष तक हमने सच्चाई तथा निरंतरता से इस नीति का अनुसरण किया है क्योंकि इसका निर्धारण पूरे विचार विमर्श और विश्लेषण के बाद हुआ था। चीनियों और तिब्बतियों का दूरगामी हितों, एशिया में सह अस्तित्व और पर्यावरण रक्षा के लिए तिब्बत में तथा तिब्बत से बाहर रह रहे अनेक तिब्बतियों और बहुत से देशों से इस नीति को व्यवहारिक स्तर पर अनुमोदन और समर्थन मिला है।

समस्त तिब्बतियों के लिए वास्तविक राष्ट्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने के मेरे सुझाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हान जाति की दादागीरी और क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की भावनाओं को समाप्त करके तिब्बतियों और चीनियों के बीच वास्तविक बराबरी पाना। दोनों राष्ट्रीय इकाइयों को पारस्परिक सहायता, विश्वास और मैत्री से देश की स्थिरता को बल मिलेगा तथा हमारी समृद्ध संस्कृति तथा भाषा के रख रखाव का भी जिसका आधार होगा समस्त मानवता के हित में आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास के बीच सही संतुलन।

निस्संदेह चीनी संविधान में अल्पसंख्यक राष्ट्रीय इकाइयों को राष्ट्रीय प्रादेशिक स्वायत्तता देने का

प्रावधान है। समस्या यह है कि पूरी तरह इसका कार्यान्वयन नहीं होता जिससे अल्पसंख्यक इकाईयों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण करने के उद्देश्य में यह प्रावधान असफल रहता है। जमीनी असलियत यह है कि बहुसंख्यक राष्ट्रीय इकाई की भारी संख्या ने इन अल्पसंख्यक इकाइयों के इलाकों में पैर पसार लिए हैं। इसलिए अपने दैनिक जीवन में अल्पसंख्यक इकाइयों के बजाए अपनी पहचान, संस्कृति और भाषा को सुरक्षित रखने के बहुसंख्यक इकाई की भाषा और रीति रिवाजों पर निर्भर रहने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। फलतः यह खतरा है कि धीरे–धीरे अल्पसंख्यक राष्ट्रीय इकाइयों की भाषाएं तथा समृद्ध परंपराएं कहीं समाप्त न हो जाएं।

ढांचागत विकास में अपनी कोई खराबी नहीं जैसे कि रेलवे में। लेकिन अत्यंत चिंता का विषय है कि जब से रेल चालू हुई है तिब्बत में और अधिक चीनी जनसंख्या स्थानांतरित हुई है। पर्यावरण में गिरावट आई है। जल का दुरुपयोग और प्रदूषण बढ़ गया है। प्राकृतिक संसाधनों का दुर्दोहन हुआ है। दससे सारे इलाके की और उन लोगों की तबाही हुई है जो लोग वहां रहते हैं।

हालांकि अल्पसंख्यक राष्ट्रीय इकाइयों में कुछ एक शिक्षित और योग्य कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य भी हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से बहुत कम को राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करने का मौका मिला है। बल्कि उनमें से कई लोगों पर तो पृथकतावादी जैसे ठप्पे भी लगाए गए हैं।

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही राष्ट्रीयताओं के सही हित के वास्ते तथा स्थानीय और केंद्रीय सरकारों के हित में सार्थक स्वायत्तता को स्थान दिया जाना उचित है। चूंकि उपरोक्त स्वायत्तता का संबंध विशेषकर अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं से है इसलिए पूरी तिब्बती राष्ट्रीयता के लिए एकछत्र प्रशासन की मांग बिल्कुल उपयुक्त, न्यायसंगत और पारदर्शी है। दुनिया जानती है कि हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। इसलिए सभी तिब्बती लोगों का यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि वे इस न्यायसंगत मांग की पूर्ति के लिए अपना संघर्ष जारी रखें।

जितना भी समय लगे, लक्ष्य पूरा होने तक हम अपना साहस और निश्चय नहीं बदलेंगे। तिब्बती जनता का संघर्ष कुछ खास व्यक्तियों के पद के लिए संघर्ष नहीं है बल्कि यह एक जन संघर्ष है। हम निर्वासित तिब्बती प्रशासन और समुदाय को पहले ही एक सच्ची प्रजातांत्रिक प्रणाली का रूप दे चुके हैं जिसके अंतर्गत अनेक बार जनता के प्रतिनिधि जनता के द्वारा बार–बार चुने जा चुके हैं।

2002 में तिब्बतियों और चीनियों के मध्य सीधी बातचीत शुरू होने के समय से मेरे प्रतिनिधि चीनी गणराज्य के संबद्ध अधिकारियों के साथ पांच दौर का विचार विमर्श कर चुके हैं। इसके दौरान दोनों पक्षों ने स्पष्ट शब्दों में उन संदेशों, शंकाओं और वास्तविक कठिनाइयों का जिक्र किया जो दोनों देशों के बीच है। इस प्रकार इन चर्चाओं द्वारा दोनों पक्षों के बीच एक संपर्क माध्यम के बनाने में सहायता मिली है।

तिब्बती प्रतिनिधिमंडल किसी भी समय और किसी भी स्थान पर वार्तालाप जारी रखने को तैयार बैठा है। इसका विस्तृत विवरण मंत्रिमंडल अपने वक्तव्य में देगा।

तिब्बत में रह रहे सभी तिब्बतियों, तिब्बती कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों, नेताओं, अधिकारियों, व्यवसाइयों और अन्य लोगों को मैं अपनी शुभ कामनाएं देता हूं जिन्होंने तिब्बती जनता के वास्तविक हितों के लिए काम करते हुए तिब्बती भावना को जीवित रखा। मैं उनके अपार साहस की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने तिब्बती जनता की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किया। तिब्बत में रह रहे तिब्बती जनों की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने सभी मुश्किलों के बावजूद तिब्बती अस्मिता, संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण के लिए प्रयत्न किया है। तिब्बत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके अडिग साहस और दृढ़ निश्चय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे इस साझे लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे दुगनी लगन तथा प्रतिबद्धता से प्रयत्न करते रहेंगे।

तिब्बत में तथा तिब्बत से बाहर रह रहे सभी तिब्बती लोगों से मेरा आहवान है कि राष्ट्रीयताओं के बीच समानता और समरसता पर आधारित सुरक्षित भविष्य के लिए वे सब मिल का एकजुटता से काम करें। इस अवसर पर मैं भारत की जनता तथा भारत सरकार के प्रति हमारी सहायता में उनकी निरंतर और असाधारण उदारता के लिए हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा।

मैं अंतर्राष्ट्रीय समाज की उन समस्त सरकारों तथा लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने तिब्बत के प्रश्न पर हमें सहानुभूति और समर्थन दिया है।

समस्त सत्वों की शांति और कल्याण के लिए मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं।

दलाई लामा
10 मार्च, 2007

जमीनी असलियत यह है कि बहुसंख्यक राष्ट्रीय इकाई की भारी संख्या ने इन अल्पसंख्यक इकाइयों के इलाकों में पैर पसार लिए हैं। इसलिए अपने दैनिक जीवन में अल्पसंख्यक इकाइयों के बजाए अपनी पहचान, संस्कृति और भाषा को सुरक्षित रखने के बहुसंख्यक इकाई की भाषा और रीति रिवाजों पर निर्भर रहने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। फलतः यह खतरा है कि धीरे–धीरे अल्पसंख्यक राष्ट्रीय इकाइयों की भाषाएं तथा समृद्ध परंपराएं कहीं समाप्त न हो जाएं।

दलाई लामा जी के निवास पर भारतीय सांसद के साथ – साझा संघर्ष

भारतीय जनता तिब्बत के साथ है

तिब्बती जनक्रांति की सालगिरह पर भारतीय सांसदों का आश्वासन, विश्व भर में प्रदर्शन और रैलियां

पूर्व रक्षा मंत्री और तिब्बत के जाने माने मित्र श्री जार्ज फर्नांडीज़ के नेतृत्व में 11 भारतीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने धर्मशाला की यात्रा की। इसका मुख्य उद्देश्य तिब्बती जनक्रांति की 48 वर्षगांठ के समारोहों में भाग लेना और तिब्बत की जनता के साथ भारतीय जनता की एकजुटता को व्यक्त करना था।

भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और तिब्बत के जाने माने मित्र श्री जार्ज फर्नांडीज़ के नेतृत्व में 11 भारतीय सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला की यात्रा की। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती जनक्रांति की 48 वर्षगांठ के समारोहों में भाग लेना और तिब्बत की जनता के साथ भारतीय जनता की एकजुटता को व्यक्त करना था। 1959 में इस दिन तिब्बत पर जबरन कब्जा जमाए बैठी चीनी सेना के खिलाफ तिब्बती जनता ने आंदोलन शुरू किया था। इसे कुचलने के लिए चीनी सेना ने तब 80 हजार से ज्यादा तिब्बती नागरिकों की हत्या की थी।

10 मार्च के दिन धर्मशाला के मुख्य मंदिर सुकलाखांग के प्रांगण में आयोजित मुख्य समारोह में श्री फर्नांडीज़ ने अपने भाषण में कहा कि भले ही पिछले कई साल से चलने वाले तिब्बती संघर्ष के अब तक कोई बहुत ठोस परिणाम नहीं निकले हैं पर इसके बावजूद हमें अपने प्रयासों को तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक कि तिब्बत समस्या का कोई संपूर्ण समाधान नहीं निकल आता। उन्होंने कहा कि मैं इस संघर्ष के बारे में हमेशा बहुत आशावान रहा हूं और हमेशा आशावान बना रहूंगा।

जनता दल में उनके सहयोगी सांसद और भारत–तिब्बत संसदीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री बशिष्ठ नारायण सिंह ने उपस्थित तिब्बती जनता और विदेशी मेहमानों को बताया कि भारत के सांसद हमेशा से तिब्बती संघर्ष और दलाई लामा जी के मजबूत समर्थक रहे हैं। हिमाचल में मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सांसद सुश्री प्रतिभा सिंह ने संसदीय मंच की गतिविधियों का परिचय देते हुए बताया कि तिब्बत समर्थन की दिशा में मंच ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अपने उद्बोधन में दलाई लामा जी ने चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ के सामंजस्यपूर्ण समाज के विचार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी समाज को इस स्तर तक पहुंचने के लिए स्वतंत्रता, न्याय और बराबरी के रास्ते से जाना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि तिब्बती प्रशासन पूरी निष्ठा के साथ तिब्बत के लिए वास्तविक राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करता आया है जिससे न केवल चीन–तिब्बत संबंधों को मजबूती मिलेगी बल्कि इससे अल्पसंख्यक तिब्बतियों की समृद्ध संस्कृति और भाषा भी बनी रहेंगी। इस अवसर पर तिब्बत की निर्वासन सरकार के प्रधानमंत्री प्रोफेसर सामदोंग रिंपोछे ने कहा कि हालांकि हाल ही में कुछ चीनी सरकारी अधिकारियों ने दलाई लामा जी के खिलाफ अपमान भरी टिप्पणियों और आधारहीन आरोपों की बौछार की है लेकिन इसके बावजूद तिब्बती प्रशासन चीन सरकार के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने में मजबूती के साथ लगा रहेगा।

तिब्बती जनक्रांति की 48वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर दुनिया भर में तिब्बती शरणार्थियों और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किए और रैलियां निकालीं। मुख्य समारोह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर में हुआ जहां से दलाई लामा निर्वासन तिब्बत सरकार का संचालन करते हैं। नगर में हजारों तिब्बती शरणार्थियों और उनके भारतीय और विदेशी समर्थकों ने जलूस निकाला। इस अवसर पर दलाई लामा ने अपना वार्षिक संदेश दिया। प्रदर्शन में भारत के कोने–कोने से आयी तिब्बती महिलाएं भी थीं जिन्होंने 12 मार्च को 'तिब्बती महिला दिवस' के आयोजनों में भी भाग लिया।

इस अवसर पर दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, मनाली, बंगलोर, मैसूर, कोलकाता, अहमदाबाद, अरुणांचल प्रदेश और कालिंपोंग समेत दर्जनों स्थानों पर तिब्बतियों और उनके भारतीय समर्थकों ने जलूस निकाले और सभाएं कीं। उदाहरण के लिए शिमला में 600 से अधिक लोगों ने लगभग 13 किमी लंबा जलूस निकाला। दिल्ली में जंतर–मंतर पर हुए मुख्य प्रदर्शन के अलावा तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चीनी दूतावास पर प्रदर्शन किया और उसके कुछ कार्यकर्ता दूतावास में घुसने में सफल रहे। मेरठ से श्री कुल भूषण बक्शी के मार्गदर्शन में चलने

वाले अंतर्राष्ट्रीय भारत–तिब्बत सहयोग समिति ने इस साल 10 मार्च के समारोह का अयोजन 30 किमी दूर मवाना में लक्ष्मी देवी आर्या महिला कालेज में किया। इसमें नगर के सौ से अधिक जागरुक नागरिकों के अलावा डा. आनंद कुमार, और सुश्री यूडोन आउकात्सांग ने भी भाग लिया।

जर्मनी में 783 नगर पालिकाओं पर तिब्बत का झंडा

जर्मनी के तिब्बत समर्थक संगठनों ने पिछले 12 साल से चलने वाले अभियान के तहत इस बार 10 मार्च के अवसर पर वहां की नगर पालिकाओं के सहयोग से 783 मेयर भवनों पर तिब्बत का झंडा लहराया। इस अभियान की संचालिका मोनिका दाईमान ने कहा कि यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में जर्मन सरकार से हम विशेष अपील कर रहे हैं कि वह तिब्बत को अपना सक्रिय समर्थन दे। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल तिब्बती जनता के मानवाधिकारों के लिए नहीं है बल्कि यह तिब्बती जनता के न्यायपूर्ण संघर्ष के प्रति समर्थन है।

दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शन

12 मार्च के दिन केप टाउन में 30 से अधिक तिब्बत समर्थकों ने एक जुलूस निकाला। इसका आयोजन टिबेट–अफ्रीका रेनबो एलायंस (तारा) ने किया था। प्रदर्शनकारी अपने साथ दलाई लामा और नेलसन मंडेला के बड़े चित्रों तथा तिब्बती झंडों के अलावा बड़े–बड़े बैनर लिए हुए थे। बैनरों पर तिब्बत की आजादी, पंचेन लामा की रिहाई, तिब्बत में चीनी नागरिकों को बसाए जाने के चीनी अभियान और दलाई लामा के समर्थन आदि के नारे लिखे हुए थे।

फ्रांस में 200 लोगों का प्रदर्शन

पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार फ्रांस में तिब्बत समर्थक संगठनों ने बहुत सक्रियता के साथ 10 मार्च के प्रदर्शनों का अयोजन किया। मार्सेल में दो सौ से ज्यादा तिब्बत समर्थकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आलटरनेटिव तिबेतां के मैथ्यू वैरनेर के अनुसार चीन के खिलाफ प्रदर्शन न करने की तिब्बत सरकार की अपीलों के कारण पिछले तीन चार साल से तिब्बत समर्थकों में असमंजस बना हुआ था। लेकिन इस बार प्रदर्शनकारियों ने लगातार दो घंटे तक तिब्बती आजादी के नारे लगाकर वातावरण का उत्साह से भर दिया।

न्यूयार्क, मिनिसोटा आदि में उत्साह

विदेशों में आयोजित प्रदर्शनों में कई अमेरिकी शहरों के प्रदर्शनों का स्थान काफी अलग रहा।

तिब्बती जनक्रांति के प्रति दिल्ली में समर्थन रैली – विश्व भर में समर्थन

न्यूयार्क में स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट और क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस के नेतृत्व में दो हजार से ज्यादा तिब्बत समर्थकों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मैनहट्टन की सड़कों को तिब्बती झंडों के रंगों और नारों की गूंज से सराबोर कर दिया। मिनिसोटा में 800 तिब्बत समर्थकों ने राज्य सरकार मुख्यालय के सामने मैदान में प्रदर्शन किया। ऐसे ही प्रदर्शन सान फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, लॉस ऐंजलिस और दूसरे कई शहरों में किए गए। बर्कले के प्रदर्शन में सबसे ज्यादा उत्साह चीनी कांसुलेट के सामने दिखा जहां प्रदर्शनकारी ट्रक पर लगा विशालकाय लाउडस्पीकर भी ले गए थे।

कनाडा, ताइवान, पोलैंड,रोम, स्विट्ज़रलैंड में रैलियां

इस अवसर पर कई अन्य देशों से भी प्रदर्शनों के समाचार आए हैं। कनाडा के वैनकूवर प्रदर्शन में वहां के दो सांसदों ने भी भाग लिया। ताइवान में ताइपेई सिटी काउंसिल के आसपास स्थानीय तिब्बतियों और उनके समर्थकों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पोलैंड की राजधानी वारसा में लगभग 50 लोागों ने चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया और तिब्बत में चीनी सेना द्वारा मारे गए 12 लाख तिब्बतियों को श्रद्धांजलि दी। रोम के एक मुख्य चौराहे पर सभा और प्रदर्शन किया गया। स्विट्ज़रलैंड में टिबेटन यूथ एसोसिएशन ने एक अनूठा प्रयोग करते हुए बेर्न में चीनी दूतावास की दीवारों को रातोंरात तिब्बती झंडे के रंगों से पेंट कर दिया। जेनेवा में भी भारी संख्या में आए तिब्बत समर्थकों ने जुलूस निकाला। लंदन में स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट के नेतृत्व में चीनी दूतावास से प्रधानमंत्री निवास के बीच जोरदार रैली निकाली गई।

पोलैंड की राजधानी वारसा में लगभग 50 लोागों ने चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया और तिब्बत में चीनी सेना द्वारा मारे गए 12 लाख तिब्बतियों को श्रद्धांजलि दी। रोम के एक मुख्य चौराहे पर सभा और प्रदर्शन किया गया। स्विट्ज़रलैंड में टिबेटन यूथ एसोसिएशन ने एक अनूठा प्रयोग करते हुए बेर्न में चीनी दूतावास की दीवारों को रातोंरात तिब्बती झंडे के रंगों से पेंट कर दिया।

चीनी दूतावास की दीवार पर शिबयान राहा – जीवट भरा समर्थन

चीनी दूतावास में घुसने के प्रयास में भारतीय और तिब्बती छात्र गिरफ्तार

पंचेन लामा के जन्मदिन पर उनकी रिहाई के समर्थन में अनूठा प्रदर्शन, जेल में दोनों का अनशन

उनका कहना है कि राजदूत से मिलने की अनुमति नहीं मिलने के बाद ही उन्होंने दूतावास में जबरदस्ती प्रवेश की कोशिश की। उन्होंने मांग की कि उन पर लगे आरोप भी वापस लिये जायें क्योंकि वे अपराध नही कर रहे बल्कि तिब्बत की आजादी के लिये लड़ रहे हैं।

नयी दिल्ली, नौ अप्रैल तिब्बत के समर्थन में इस बार राष्ट्रीय राजधानी में एक अनूठा प्रदर्शन हुआ। चाणक्यपुरी स्थित चीनी दूतावास में प्रवेश की कोशिश करने वाले एक भारतीय तिब्बत समर्थक शिबयान राहा तथा एक तिब्बती युवक मिगमार सेरिंग को को गिरफ्तार कर लिया गया। सेरिंग मजनूं का टीला स्थित तिब्बती शरणार्थी बस्ती में रहते हैं जबकि राहा फ्रेंड्स फार तिब्बत की कोलकाता शाखा के साथ काम करते हैं।

राहा, फ्रेंड्स फार तिब्बत के अभियान समन्वयक तथा सेरिंग कार्यकर्ता हैं। ये दोनों, ग्यारहवें पंचेन लामा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। पंचेन लामा को चीन सरकार ने पिछले 12 साल से कहीं नजरबंद किया हुआ है। तिब्बती समुदाय में पंचेन लामा को परम पावन दलाई लामा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व माना जाता है।

यह अपनी तरह की एक अनूठी घटना है जब इस मांग को लेकर किसी गैर तिब्बती ने इतना साहसिक कदम उठाया। यह विरोध कार्रवाई पंचेन लामा के आगामी जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले की गई है। पंचेल लामा इस साल 25 अप्रैल को 18 साल के होने वाले हैं। दलाई लामा द्वारा उन्हें अगले पंचेन लामा के रूप में मान्यता दिये जाने के बाद से ही चीन ने 1995 से उन्हें गिरफ्तार कर रखा गया है। उस समय वे मात्र छह साल के थे। लेकिन विश्व स्तर पर विरोध एवं सतत अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।

राहा ने इस घटना के समय 'फ्री तिब्बत – फ्री पंचेन लामा ' के नारे वाली टीशर्ट पहन रखी थी। हाथ में तिब्बत का राष्ट्रीय ध्वज लिये राहा और सेरिंग ने पहले दूतावास के गेट के सामने ' तिब्बत को मुक्त करो ' एवं ' पंचेन लामा को रिहा करो ' के नारे लगाए और इसके बाद दूतावास के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े। जब उन्होंने वहां की तारबंदी पर चढ़ने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया।

राहा ने इससे पहले 23 नवंबर 2006 को चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ के अभिभाषण से पहले मुंबई के ताज होटल के बाहर प्रदर्शन किया था। तब उन्होंने कहा था कि ''भारतीय के रूप में मैं शर्मिंदा हूं कि भारत सरकार तिब्बत के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है।''

शिबयान राहा तथा मिगमार सेरिंग को चाणक्यपुरी पुलिस थाने में रखा गया और बाद में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने 12 अप्रैल को समाचार दिया कि शिबयान और मिगमार सेरिंग अपनी गिरफ्तारी के दिन से ही भूख हड़ताल पर हैं। इन दोनों का कहना है कि वे मांगे माने जाने तक आमरण अनशन करेंगे। इन तिब्बत समर्थकों का कहना है कि वे भारत में चीन के दूतावास में राजदूत सुन युक्सी को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन देना चाहते हैं। इनकी मांग है कि ग्यारहवें पंचेन लामा, गेंदुन छ्युकी नीमा को चीन सरकार की कैद से रिहा किया जाये।

इनकी यह भी मांग है कि पंचेन लामा को तिब्बत में ताशी लुपो मठ में उनके परंपरागत पद पर बहाल किया जाये। उनका कहना है कि राजदूत से मिलने की अनुमति नहीं मिलने के बाद ही उन्होंने दूतावास की दीवार फांद कर जबरदस्ती प्रवेश की कोशिश की। उन्होंने मांग की कि उन पर लगाये गये आरोप भी वापस लिये जायें क्योंकि वे अपराध नही कर रहे बल्कि तिब्बत की आजादी के लिये लड़ रहे हैं।

तिहाड़ जेल के विधि अधिकारी सुनील कुमार ने एक्सप्रेस को बताया कि ''हम उनके स्वास्थ्य पर निगाह रखे हैं और आवश्यकता होने पर एहतियाती कदम उठाये जा सकते हैं।'' उनकी वकील जयश्री ने बताया कि दोनों को जेल के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में कुछ दिन बाद दोनों को रिहा कर दिया गया।

फोटो : विजय क्रान्ति

बेलजियम की एक सभा में प्रो. सामदोंग रिंपोछे : राष्ट्रीय पहचान की चिंता

आर्थिक उदारीकरण ने राजनीतिक तानाशाही की सहायता ही की है

भारत में तिब्बती पहचान को बचाए रखने में हमें पूरी सफलता मिली है – प्रो. रिंपोछे

निर्वासित तिब्बत सरकार के चैयरमेन प्रोफेसर समदोंग रिंपोछे को तिब्बती संस्कृति एवं शिक्षा के दिशा में किये गये कार्यों के लिये जाना जाता है। तिब्बती समुदाय की प्रगति में उनकी अहम् भूमिका रही है। करीब दस साल तक निर्वासित तिब्बती संसद के चैयरमेन रहे प्रोफेसर रिंपोछे उस समिति के सदस्य रहे हैं जिसने भविष्य के तिब्बत के संविधान की रचना की है। गांधीवादी विचारक एवं दार्शनिक प्रो रिंपोछे तिब्बती समुदाय एवं तिब्बत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर उनका यह साक्षात्कार *राजस्थान पत्रिका* से साभार –

– भारत में तिब्बती समुदाय के हालात से क्या आप खुश हैं?

बिलकुल, मैं बेहद खुश हूं। आज भारत में एक लाख से ज्यादा तिब्बती निवास करते हैं और हमें भारत की जनता से पूरा समर्थन हासिल है। भारत सरकार के समर्थन और सहयोग से तिब्बत के लोग अपनी संस्कृति एवं परंपरा को बचाने रखने में कामयाब हो पाए हैं। वास्तव में तिब्बती संस्कृति को बचाये रखना ही हमारे आंदोलन का मूल उद्देश्य है।

– तिब्बती आंदोलन का भविष्य क्या है? चीन के साथ समझौते को लेकर आप कितने आशान्वित हैं?

फिलहाल चीन के साथ किसी तरह का संवाद नहीं है, मगर उम्मीद है कि इस साल बातचीत शुरू हो पायेगी। यदि इस मुद्दे का कोई हल निकल पाता है तो बहुसंख्यक तिब्बती फिर से तिब्बत लौटना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार के हल की संभावना नहीं बनती है तो यह समुदाय तिब्बत से बाहर ही रहना चाहेगा।

– बाजार आधारित अर्थव्यवस्था एवं उदारीकरण को अपनाने के बाद क्या आप चीन के रुख में किसी तरह का बदलाव देखते हैं?

चीन की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेहद खराब किस्म की है, लिहाजा उसके रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं है। उदारीकरण से चीनी सरकार की तानाशाही नीतियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है। वास्तव में आर्थिक उदारीकरण ने राजनीतिक तानाशाही की सहायता ही की है। इस समय पूरा पश्चिमी जगत चीन की तानाशाही से खुश है क्योंकि इससे प्रशासन में पारदर्शिता खत्म हुई है, जो इन देशों के साथ व्यापार के लिये मददगार है।

– भारत में रह रही तिब्बती जनता का भविष्य क्या है?

हम लोग यहां पिछले 47 साल से रह रहे हैं। कई लोगों का तो जन्म ही भारत में हुआ है और उन्होंने अपने को इस नये घर में समायोजित कर लिया है। यहां कई परिवार हैं जो भारतीयों की तरह जीवन गुजारते हैं और भारतीय भाषाएं बोलते हैं।

– क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय मुख्यधारा में शामिल होने से तिब्बती समुदाय की पहचान के समाप्त होने का खतरा है?

नहीं, मुझे ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता। अधिकांश तिब्बती यहां समुदायों में रहते हैं। करीब 40 हजार तिब्बती फिलहाल कर्नाटक में पांच तिब्बती बस्तियों में रह रहे हैं। यह समुदाय साथ रहने में यकीन करता है और अपनी परपंरा – संस्कृति को भी बचाये हुए है।

– दलाई लामा और आपके बाद तिब्बत का नेतृत्व क्या होगा?

हमारी व्यवस्था में नेतृत्व चुनाव के जरिये तय होता है। हरके पांच वर्ष बाद जनता नए सिरे से अपने राजनीतिक नेतृत्व को चुनती है। लेकिन जहां तक धार्मिक नेतृत्व की बात है तो दलाई लामा के बाद एक वैकल्पिक नेतृत्व की नियुक्ति की स्पष्ट व्यवस्था है। नए अवतार की पहचान और उनके वयस्क होने तक कार्यकारी मंडल का चयन विभिन्न समुदायों के प्रमुखों में से किया जाता है। धार्मिक नेतृत्व को लेकर कोई समस्या नहीं है।

(–सेन सेबेस्टियन)

वास्तव में आर्थिक उदारीकरण ने राजनीतिक तानाशाही की सहायता ही की है। इस समय पूरा पश्चिमी जगत चीन की तानाशाही से खुश है क्योंकि इससे प्रशासन में पारदर्शिता खत्म हुई है, जो इन देशों के साथ व्यापार के लिये मददगार है।

तिब्बत की कहानी –

1. चीन में ओलंपिक खेलों के आयोजन के विरोध में हालैंड के तिब्बत समर्थकों की मास्टरि
2. 12 मार्च को तिब्बती महिला दिवस के अवसर पर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के
3. पंचेन लामा के 18वें जन्म दिवस पर उनकी रिहाई के लिए चीनी दूतावास पर प्रदर्शन क
4. पैरिस में तिब्बत समर्थकों ने पंचेन लामा की चीनी हिरासत से रिहाई के लिए 21 अप्रेल
5. पंचेन लामा की रिहाई की मांग करते हुए तिब्बत के भारतीय समर्थकों ने 16 अप्रेल को
6. 10 मार्च को तिब्बती जनक्रांति की वर्षगांठ के सिलसिले में ओटावा, कनाडा में कनाडा
7. वसंत–उपदेश के अंतर्गत दलाई लामा ने आचार्य शांति देव की शिक्षाओं के आधार पर
8. यूथ लिबरेशन फ्रंट आफ तिब्बत के कार्यकर्ताओं ने पंचेन लामा की रिहाई के लिए नई
9. तिब्बत और चीन बातचीत के बारे में अमेरिकी विदेश समिति की सुनवाई में दलाई लाम
10. 10 मार्च को तिब्बती जनक्रांति की वर्षगांठ के मौके पर ताइवान में हुए एक प्रदर्शन में

— कैमरे की जुबानी

श्ट से हेग तक 270 किमी यात्रा का समापन 10 मार्च को चीनी दूतावास के सामने हुआ।
सामने प्रदर्शन करते तिब्बत समर्थक।
करने वाले शिबयान राहा को गिरफ्तार करके ले जाता दिल्ली पुलिस का अधिकारी।
को जुलूस निकाला।
नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया।
टिबेट कमेटी और स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट ने चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया।
बोधिसत्वों की जीवनशैली के बारे में उपदेश दिया जिसमें देश–विदेश से लोग आए।
दिल्ली में 16 अप्रेल के दिन प्रदर्शन किया।
जी के दूत श्री लोडी ग्यारी, श्री रिचर्ड गेअर ने पाउला गोब्रिएंस्की ने भाग लिया।
तिब्बती झंडे और दलाई लामा के चित्र के साथ प्रदर्शनकारी।

(फ़ोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

चीन सरकार और दलाई लामा में बातचीत को यूरोपीय संघ संसद का समर्थन

चीन न माने तो अगली कार्रवाई पर विचार

तिब्बत के हालात में हाल ही के वर्षों में खासी रुचि दिखाने वाले यूरोपीय संघ ने दलाई लामा और चीन की सरकार में बातचीत की प्रक्रिया बहाल करने का आग्रह किया है। यूरोपीय संसद (एमईपी) ने इस संबंध में एक प्रस्ताव हाल ही में पारित किया।

उल्लेखनीय है कि चीन एवं तिब्बत के निर्वासित शासक और वहां के शीर्ष धार्मिक गुरु दलाई लामा में बातचीत की प्रक्रिया सितंबर 2002 में शुरू हुई थी जो पिछले 12 माह से स्थगित है।

यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों से कहा गया है कि वे बातचीत को मजबूत करने के लिये संपूर्ण समर्थन दें और किसी तरह का ठोस परिणाम सामने नहीं आने की स्थिति में यह आकलन करें कि तिब्बत के लिये उचित समाधान सामने लाने के लिये यूरोपीय संघ क्या कर सकता है। इस स्थिति के लिये दिये गये सुझावों में तिब्बत के लिये यूरोपीय संघ के एक विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति भी शमिल है।

यूरोपीय संसद ने इस आशय के प्रस्ताव को 71 –0 मतांतर से स्वीकृत किया। एक सदस्य ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव में 'तमाम मतभेदों के बावजूद' तिब्बती मुद्दे का समाधान बातचीत के रास्ते से सुलझाने की चीन सरकार तथा दलाई लामा की प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया है।

संसद ने चीन सरकार एवं दलाई लामा से आग्रह किया है कि बातचीत को बहाल किया जाये और इसे बिना किसी पूर्व शर्त के भविष्योन्मुखी रवैये के साथ जारी रखा जाये ताकि इस तरह का समाधान सामने आ सके जो चीन की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करने वाला तथा तिब्बती जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला हो।

संसद ने चीन सरकार द्वारा अंगीकृत 'क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता संबंधी नियमों एवं कानूनों का स्वागत किया है।'

तिब्बत के लिये विशेष प्रतिनिधि?

यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों से कहा गया है कि वे बातचीत को मजबूत करने के लिये संपूर्ण समर्थन दें और किसी तरह का ठोस परिणाम सामने नहीं आने की स्थिति में यह आकलन करें कि तिब्बत के लिये उचित समाधान सामने लाने के लिये यूरोपीय संघ क्या कर सकता है। इस स्थिति के लिये दिये गये सुझावों में तिब्बत के लिये यूरोपीय संघ के एक विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति भी शमिल है।

इसके अलावा तिब्बती मुद्दे को नये यूरोपीय संघ और चीन की सहभागिता एवं सहयोगी ढांचा करार की बातचीत में भी उठाने का आहवान किया गया। इस करार पर आधिकारिक बातचीत 17 जनवरी 2007 को बीजिंग में शुरू हुई। इस नये करार के लिये दोनों पक्षों की बातचीत में तिब्बत के मुद्दे को उठाने की मांग की गई।

इसके अलावा संसद में इस आशय के घोषणा पत्र को अंगीकृत करने का सुझाव दिया गया कि यूरोपीय संघ तिब्बत मुद्दे के शांतिपूर्ण एवं बातचीत के रास्ते समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिये क्या करेगा।

कनाडा संसद में भी प्रस्ताव

कनाडा की संसद ने भी एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसमें 'चीन सरकार एवं निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रतिनिधियों से सकारात्मक रवैये के साथ बातचीत जारी रखने का आग्रह करने की बात कही गई है। इस आशय का प्रस्ताव टोरंटो से सांसद सदस्य श्रीमती पेगी नैश ने पेश किया।

स्काटलैंड संसद का प्रस्ताव

स्काटिश संसद में चीन – तिब्बत बातचीत प्रक्रिया पर एक प्रस्ताव 26 फरवरी 2007 को पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में 'चीनी संवैधानिक ढांचे तथा चीन की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करते हुए तिब्बती लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाले एक व्यावहारिक समाधान' का प्रयास करने का आहवान किया गया है।

तिब्बती प्रधानमंत्री की अमेरिका में चीनी विद्वानों के साथ बैठक

तिब्बती मंत्रिमंडल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री (कालोन ट्रीपा) प्रोफेसर सामदोंग रिंपोछे ने हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी में लगभग आधा दर्जन ऐसे विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया जो अमेरिका के विश्वविद्यालयों में या चीन में अनुसंधान और अध्यापन कार्य में लगे हैं।

लगभग चार घंटे चली इस बैठक में तिब्बती समस्या के समाधान एवं चीनी सरकार की स्थिति तथा तिब्बती नेतृत्व के रुख आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

बंद दरवाजों में हुई इस बैठक की मेजबानी बुकिंग इंस्टीट्यूशन ने की। इंस्टीट्यूट में पहुंचने पर कालोन ट्रीपा का स्वागत संस्थान में विदेशी नीति अध्ययन के सीनियर फेलो जान एल थ्रोंटन ने किया।

कालोन ट्रीपा के साथ तिब्बती दल में विषेष दूत लोडी ग्यारी, कासूर ताशी वांगदी, दूत केलसांग ग्यालतसेन, लैटिन अमेरिका के लिये तिब्बत के समन्वय अधिकारी सेवांग फुंतसोक, पेमा वांग्याल, तिब्बत के लिये अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईसीटी) के रिंछेन ताशी एवं भुचुंग सेरिंग शामिल थे। कालोन ट्रीपा ने

बादमें आईसीटी के सम्मेलन कक्ष में तिब्बती समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने चीन–तिब्बत बातचीत प्रक्रिया पर तिब्बती प्रशासन के रवैये एवं तिब्बती संघर्ष के भविष्य पर विचार रखे। वहीं दोनों पक्षों में बातचीत के बाद सवाल–जवाब सत्र हुआ।

प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष से मुलाकात

प्रोफेसर सामदोंग रिंपोछे ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नेंसी पेलोसी से शिष्टाचार भेंट की। पेलोसी लंबे समय से दलाई लामा जी की मित्र हैं और संसद में तिब्बती मामलों की समर्थक रही हैं। अध्यक्ष ने कलोन ट्रीपा एवं विषेष दूत लोडी ग्यारी का गर्मजोशी से स्वागत किया और दलाई लामा के साथ अपनी आगामी बैठक की योजनाओं पर विचार विमर्श किया।

विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष टाम लेंटोस ने भी कलोन ट्रीपा से मुलाकात की और कहा कि समिति द्वारा अमेरिकी–चीन नीति की समीक्षा के दौरान तिब्बत प्राथमिकता होगा। उन्होंने कहा कि वे दलाई लामा के दूतों एवं चीनी अधिकारियों के बीच बातचीत की मौजूदा स्थिति के बारे में सुनवाई अगले ही कुछ हफ्तों में करने के इच्छुक हैं।

तिब्बती नेता वाशिंगटन की एक सप्ताह की यात्रा पर थे। जून 2006 में कलोन ट्रीपा के रूप में पुनः चुनाव के बाद उनकी यह पहली अमेरिका यात्रा थी।

प्रो. रिंपोछे ने नेशनल इनडोवमेंट फार डेमोक्रेसी, एन ई डी का भी दौरा किया और अध्यक्ष कार्ल ग्रेशमेन से मिले। एनईडी दलाई लामा के तिब्बत की निवार्सित सरकार, सीटीए के धर्मशाला स्थित मुख्यालय को अनुदान सहायता मुहैया कराता है।

रिंपोछे ने कहा, ''चीन से राजनीतिक अलगाव महत्वपूर्ण नहीं है ... महत्वपूर्ण यह है कि तिब्बती सभ्यता की बहाली हो। तिब्बत महज एक देश या राज्य नहीं है बल्कि यह एक अनूठी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर है। इसे चीन में भी संरक्षित किया जा सकता है या इसे हम चीन से अलग होकर भी संरक्षित नहीं रख सकते। हमारा मूल उद्देश्य मानवता के हित में इसे भविष्य में सुरक्षित रखना है।''

टोरंटो में तिब्बतियों ने लोबसांग को याद किया

टोरंटो, खून जमा देने वाली सर्दी और शून्य से दस डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के बावजूद टोरंटो में तिब्बती महिलाओं के संगठन : टीडब्ल्यूओटी ने लोबसांग धोंधुप को अन्यायपूर्ण कारणों से फांसी दिये जाने की चौथी वर्षगांठ पर चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर मोमबत्तियां जलाईं।

उल्लेखनीय है कि लोबसांग को चीनी अधिकारियों ने 23 जनवरी 2003 को मौत की सजा दे दी थी।

इस अवसर पर संगठन के सदस्यों के साथ साथ अन्य तिब्बती एवं कनाडाई समर्थक भी मौजूद थे। इन्होंने लोबसांग की आत्मिक शांति के लिये प्रार्थना की। इसी तरह तुलकू तेनजिन डेलेक की सुरक्षा की प्रार्थना भी की गई जो अब भी जेल में हैं।

संगठन की अध्यक्ष श्रीमती सेरिंग नोरजोम थोनसुर, महासचिव श्रीमती ल्हादेन ने समूचे घटनाक्रम की जानकारी दी और तिब्बत में चीन के मानवाधिकार हनन को लोगों के समक्ष रखा।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के माइकल क्रेग ने कहा,''एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि चीन की सरकार को तिब्बत में मानवाधिकार हनन के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।'' उन्होंने चीन से तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों का आदर करने का आह्वान किया।

तिब्बतियों और यहूदियों ने अपने कष्ट के अनुभव बांटे

इटली तिब्बती एवं यहूदी समुदाय ने नाजी शासन के अधीन यहूदियों तथा कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बतियों के उत्पीड़न पर अपने अनुभव बांटे।

दोनों समुदायों का मानना है कि हालांकि यहूदियों का उत्पीड़न नाजी शासन के अधीन हुआ पर दुर्भाग्य से तिब्बती तो आज भी भुक्तभोगी हैं। यह आयोजन पूर्वी इटली के शहर तोरिनो में, वहां के सबसे पुराने थियेटर में हुआ।

यहूदी विषेशज्ञ एवं लेखक डेन सेगरे ने यहूदी संकट की बात की। वे स्विस यूनिवर्सिटी में इंस्टीटयूट आफ मेडिटेरियन स्टडीज के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर हैं। इसी तरह चीनी शासन में 33 साल तक जेल में रहे पूर्व राजनीतिक कैदी भिक्षु पालदेन ग्यात्सो ने तिब्बत में जातीय संहार के बारे में अपनी कहानी सुनाई।

इस खुली परिचर्चा का संचालन विख्यात पत्रकार गेउ लरनर ने किया। बहस में न केवल यहूदी एवं तिब्बतियों की समस्या का जिक्र हुआ बल्कि इसने मौजूदा जातीय, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मुद्दों को भी छुआ।

खून जमा देने वाली सर्दी और शून्य से दस डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के बावजूद टोरंटो में तिब्बती महिलाओं के संगठन : टीडब्ल्यूओटी ने लोबसांग धोंधुप को अन्यायपूर्ण कारणों से फांसी दिये जाने की चौथी वर्षगांठ पर चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर मोमबत्तियां जलाईं। उल्लेखनीय है कि लोबसांग को चीनी अधिकारियों ने 23 जनवरी 2003 को मौत की सजा दे दी थी।

नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों के साथ रिचर्ड गेअर : पुराना मित्र

रिचर्ड गेअर तिब्बती बस्ती पहुंचे

उत्साहित भिक्षुओं के साथ फोटो खिंचवाए

मैसूर हालीवुड के प्रख्यात अभिनेता रिचर्ड गेअर अचानक बालकुप्पे की एक तिब्बती बस्ती में पहुंचे तो वहां के ताशिलुंपो विहार के भिक्षु आश्चर्यचकित रह गये। गेअर का बालकुप्पे में आगमन उसी दौरान हुआ जब दलाई लामा भी एक नये भवन की आधारशिला रखने वहां आये हुए थे। गेअर अपनी पत्नी कोरे लावेल के साथ, दलाई लामा के आने से पहले विहार पहुंचे और वहां मौजूद भिक्षुओं से घुल मिल गये।

भिक्षुओं में गेअर के साथ हाथ मिलाने की होड़ सी मच गई और कई भिक्षु तो उनके साथ फोटो खिंचवाने में भी सफल रहे। दलाई लामा के काफिले के वहां पहुंचते ही गेअर एक किनारे खड़े हो गये और अपने डिजिटल कैमरे से दलाई लामा के फोटो लिये। बाद में वे विहार के अंदर गये और कार्यक्रम में अन्य भिक्षुओं तथा वरिष्ठ आगंतुकों के साथ बैठे जिनमें मैसूर के उपायुक्त सेलवा कुमार भी थे।

इस प्रार्थना सभा की अध्यक्षता स्वयं दलाई लामा ने की और गेअर इसमें लगातार मौजूद रहे। बाहर संवाददाताओं से बातचीत में गेअर ने कहा कि वह तिब्बत के पुराने मित्र हैं। उन्होंने कहा कि दलाई लामा उनके 'दोस्त एवं शिक्षक' हैं।

बौद्ध दर्शनशास्त्र की चर्चा करते हुए गेअर ने कहा कि इसमें 'आत्मा' की धारणा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, ''वहां तो हृदय से अनुभव की बात है और हर कोई इससे संबद्ध रहता है।''

गेअर ने बताया कि वे भारत में हीरोज़ परियोजना से भी जुड़े हैं जो एड्स के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिये समन्वित प्रयासों पर जोर देती है। उन्होंने एड्स के बारे में अनेक भारतीयों में गलत धारणा पर खेद जताया और कहा कि इस संबंध में जागरुकता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ''अगर मैं, आप मीडिया के लोग, सरकार और गैर सरकारी संगठन मिलकर काम कर सकें तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं।''

हिमाचल पुलिस का दलाई लामा की सुरक्षा को खतरे से इनकार

दलाई लामा को लष्कर ए तैयबा सहित कुछ आतंकवादी संगठनों से खतरे के समचारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने धर्मशाला में उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी है।

धर्मशाला में राज्य पुलिस के उपमहानिरीक्षक (उत्तरी क्षेत्र) पी एल ठाकुर ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि स्थानीय मीडिया में इस तरह की खबरें छपी हैं कि दलाई लामा को अल कायदा से सम्बद्ध इस्लामी चरमपंथी संगठन लश्कर–ए–तैयबा सहित अन्य आतंकवादी संगठनों से खतरा है।

ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इन रपटों को देखा है और एहतियात के तौर पर दलाई लामा की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से इस संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। पुलिस उपमहानिरीक्षक ने इन खबरों की जांच के आदेश दिये हैं।

दलाई लामा की सुरक्षा का काम उनके व्यक्तिगत स्टाफ के साथ साथ हिमाचलप्रदेश पुलिस देखती है।

संवाद समिति रायटर्स ने 15 अप्रैल को दी खबर में कहा है कि पुलिस को दलाई लामा को खतरे के बारे में खबरों की सत्यता के बारे में अभी सुरक्षा एजेंसियों से पुष्टि करनी है। स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों में कहा गया था कि लश्कर–ए–तैयबा 71 वर्षीय दलाई लामा को निशाना बनाने की फिराक में है। इस खतरे का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। दलाई लामा के सुरक्षा कार्यालय ने इन रपटों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियां स्थापित

भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को परमपावन दलाई लामा ने बोधगया में नवनिर्मित महाबोधी सोसायटी मंदिर 'जय श्री महाबोधी विहार' में स्थापित किया। इन

पवित्र अस्थियों को श्रीलंका से लाया गया है।

इसी तरह भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों सारीपुत एवं मुदगलयान की पवित्र अस्थियों को भी मंत्रों के उच्चारण के बीच स्थापित किया गया। इन्हें कोलकाता से यहां लाया गया है।

इस अवसर के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आर एस गवई थे। दलाई लामा की यात्रा को ध्यान में रखते हुए कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। दलाई लामा ने भी महाविहार में प्रार्थना की और वज्रासन के निकट स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन भी किये।

महाबोधि सोसायटी आफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों के साथ पांच श्रीलंकाई भिक्षु बोधगया पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन भगवान बुद्ध के 2550वीं जयंती समारोहों के तहत किया गया।

सारीपुत एवं मुदगलयान के अवशेष अलेक्जेंद्र कनिंगम ने सांची में 1851 में खोजे थे और तब से ये महाबोधि सोसायटी आफ इंडिया के मुख्यालय में थे।

डेसमंड टुटू की तिब्बती टिप्पणी से भारत सरकार की घबराहट

आर्कबिशप डेसमंड टुटू ने भारत के शीर्ष अंतरराष्ट्रीय सम्मान गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद तिब्बत और दलाई लामा के प्रति समर्थन जताकर भारत सरकार के अधिकारियों और नेताओं को चकित कर दिया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से नयी दिल्ली में एक भव्य समारोह में यह सम्मान पाने के बाद टुटू ने समारोह में मौजूद भारतीय नेताओं से कहा, ''एक महामानव दलाई लामा को शरण देने के लिये हम आपका धन्यवाद करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि आपकी मदद तिब्बत में आजादी लायेगी।''

उनकी इस टिप्पणी पर चीनी दूतावास की प्रतिक्रिया से घबराए हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि ''भारत 'एक चीन' की धारणा का समर्थन करता है और टुटू द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं।''

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक और नोबेल पुरस्कार विजेता पौलेंड के पूर्व राष्ट्रपति लेख वालेज़ा ने भी तिब्बत की आजादी का आह्वान किया है। उनका मानना है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह में विश्वास रखने वाले देशों को चीन पर तिब्बत की आजादी के लिये दबाव बनाना चाहिए।

तिब्बत को भारतीय समर्थन जारी रहेगा

जयपुर में हिमालय परिवार और भारत–तिब्बत सहयोग मंच की बैठक

भारत तिब्बत सहयोग मंच एवं हिमालय परिवार ने 'तिब्बत के लिये सघन अभियान' के तहत राजस्थान में अपनी बैठक की। इस अभियान के तहत ये दोनों संगठन इस तरह की बैठकों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। कोर ग्रुप फार तिबेतन कॉज़ ने इस तरह की पहली बैठक दिल्ली में की थी।

जयपुर में यह कार्यक्रम चैंबर आफ कामर्स हाल में हुआ। इसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य ज्ञानप्रकाश पिलानिया थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में पायनियर के मुख्य संपादक एवं राज्यसभा के नामांकित सदस्य डा चंदन मित्रा, डा सुरेश पटौदिया, अशोक परनामी, मंच के इंद्रेश कुमार, कोर ग्रुप फार तिबेतन काज़ के राष्ट्रीय समन्वयक कुलदीप चंद अग्निहोत्री एवं भारत तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) के सेरिंग दोरजी थे। बैठक में 40 तिब्बती स्वेटर विक्रेताओं सहित 150 लोग उपस्थित थे।

श्री पिलानिया ने '2007 : तिब्बत के लिये सघन अभियान' के स्टिकर एवं पोस्टर जारी किये। उन्होंने कहा कि तिब्बत की आजादी के लिये भारतीय जनता का समर्थन जारी रहेगा।

कैलाश यात्रियों के लिये खुलेगा लद्दाख में दमचोक मार्ग

चीन और भारत की सरकारों ने कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये लद्दाख में दमचोक से होकर जाने वाले एक अतिरिक्त मार्ग को खोलने पर सहमति जताई है।

चीन के विदेश मंत्री ली जुआओसिंग तथा भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति जताई गई। इससे पहले नेपाल सीमा के निकट लिपु लेख दर्रे वाले कठिन रास्ते से ही चीन इस यात्रा की अनुमति देता है।

इसके अलावा चीन के एंटी– सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण की चर्चा भी हुई। भारत और कई अन्य देशों ने चीन की इस हरकत को अंतरिक्ष तक हथियारों के फैलाव की हरकत बताते हुए इस पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन ली ने कहा कि यह पूरी तरह से तकनीकी और वैज्ञानिक कवायद थी जिसे किसी देश विशेष को ध्यान में रख कर नहीं किया गया।

गांधी शांति पुरस्कार के बाद टुटू ने समारोह में मौजूद भारतीय नेताओं से कहा, ''एक महामानव दलाई लामा को शरण देने के लिये हम आपका धन्यवाद करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि आपकी मदद तिब्बत में आजादी लायेगी।'' उनकी इस टिप्पणी पर चीनी दूतावास की प्रतिक्रिया से घबराए हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि ''भारत 'एक चीन' की धारणा का समर्थन करता है और टुटू द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं।''

चीन में ओलंपिक के खिलाफ प्रदर्शन : अमानवीयता का विरोध

चीन में ओलंपिक खेलों का अयोजन अनैतिक

फुटबाल मैच के दौरान तिब्बत समर्थकों का प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने चीन को ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह अनैतिक है। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले चीन को मेजबानी देकर ओलंपिक कमेटी ने चीन को ऐसा सम्मान दिया है जिसके योग्य वह नहीं है।

चीन की ओलंपिक फुटबाल टीम के चेलसी एफसी के साथ मैच के दौरान तिब्बती समर्थकों ने प्रदर्शन किया और तिब्बत में मानवाधिकार हनन तथा दमन के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

इन लोगों ने यह प्रदर्शन ग्रिफीन पार्क स्टेडियम में खेले गये इस मैच के मध्यांतर के दौरान किया। प्रदर्शनकारियों ने चीन को ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह अनैतिक है। मानवाधिकारों का हर मायने में उल्लंघन करने वाले चीन जैसे देश को इन खेलों की जिम्मदारी देकर अंतरर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने चीन को ऐसा सम्मान दिया है जिसके योग्य वह नहीं है। उनका कहना था कि चीन विभिन्न देशों एवं वर्गों में शांति, आदर तथा सद्भाव की ओलपिंक खेलों की मूल भावना का आदर नहीं करता।

प्रदर्शनकारियों ने चीन द्वारा तिब्बत में किये जा रहे दमन एवं मानवाधिकार हनन को ब्रिटेन की जनता के समक्ष रखने की कोशिश की। इस मैच को चेलसी एफसी ने एक–शून्य से जीता।

आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की दलाई लामा से मुलाकात पर विवाद

23 फरवरी, 2007 द वेस्ट आस्ट्रेलियन। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एलन कारपेंटर की दलाई लामा से मुलाकात की योजना से राजनयिक बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि चीन की सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कारपेंटर ने अपनी योजना पर अमल किया तो वे आस्ट्रेलिया के चीन के साथ मूल्यवान संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। कारोबार के लिहाज से चीन, आस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है।

वेस्ट आस्ट्रेलियन समाचारपत्र का मानना है कि तिब्बती नेता दलाई लामा के साथ मुलाकात की इच्छा जताने वाले कारपेंटर एकमात्र आस्ट्रेलियाई नेता हैं। दलाई लामा आस्ट्रेलिया की अपनी दो सप्ताह की यात्रा जून में पर्थ से शुरू करेंगे।

चीनी दूतावास के प्रतिनिधि लियू चिन ने कहा कि प्रधानमंत्री या मंत्रियों का दलाई लामा से मुलाकात करना 'उचित' नहीं है। उन्होंने कहा, ''इससे आस्ट्रेलिया एवं चीन के संबंधों में मदद नहीं मिलेगी। हमारा रवैया स्पष्ट है, वे एक अलगाववादी हैं न कि वास्तविक भिक्षु और किसी आस्ट्रेलियाई अधिकारी का उनसे मिलना उचित नहीं होगा।''

आस्ट्रेलिया के सांख्यिकी ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन, आस्ट्रेलिया का शीर्ष निर्यात बाजार बनने की राह पर है। उल्लेखनीय है कि दलाई लामा 1992 में भी आस्ट्रेलिया की यात्रा पर आये थे और इस यात्रा के दौरान भी विवाद हुआ था। तब वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जान हावर्ड ने कहा था कि वे आस्ट्रेलिया आने वाले हर धार्मिक नेता से नहीं मिलते।

वहीं आस्ट्रेलिया में दलाई लामा के कार्यकारी निदेशक एलन मालाय ने कहा है कि दलाई लामा अपनी यात्रा को गैर राजनीतिक रखने के लिये कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दलाई लामा प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा नहीं जतायेंगे लेकिन अगर उनसे ऐसी मुलाकात के लिए कहा जाता है तो उन्हें मुलाकात से खुशी होगी।

नेपाल में तिब्बती कार्यालय दुबारा नहीं खुलने दिया जाएगा : प्रचंड

नेपाल के माओवादी चरमपंथियों ने तिब्बती शरणार्थी कल्याण केंद्र : टी आर डब्ल्यू सी : को काठमांडो में अपना कार्यालय फिर खोलने की अनुमति देने की संभावना को खारिज कर दिया है।

माओवादी प्रमुख पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' का कहना है कि इसकी अनुमति दिये जाने से मित्रवत पड़ोसी चीन के साथ संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

प्रचंड ने कहा, ''हालांकि, हम नेपाल के शिविरों में कुछ समय से रह रहे शरणार्थियों को स्वदेश नहीं लौटायेंगे लेकिन उन्हें तिब्बती की आजादी के लिये अभियान चलाने के उद्देष्य से और संगठन स्थापित

करने की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि हम तिब्बत को चीन का आंतरिक हिस्सा मानते हैं।''

नेपाल एवं तिब्बत के मामलों के जानकार एक भारतीय विषेषज्ञ ने प्रचंड के इस बयान को 'आपत्तिजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण ' बताया है। उनके अनुसार प्रचंड का यह बयान इस तथ्य को साबित करता है कि प्रचंड एवं उनका संगठन चीन की कठपुतली मात्र है। उनके अनुसार प्रचंड एवं उनके सहयोगी माओवादी नेपाल को चीन की कक्षा में गतिमान उपग्रह बनाने के लिये सालों से काम कर रहे हैं। वे यह सब चीन में बैठे कम्युनिस्ट आकाओं के इशारे पर ऐसा करते आए हैं।

इस विश्लेषक ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेपाल की जनता को 'न्याय' के नाम पर चरमपंथी गतिविधियों तक का सहारा लेने वाला नेता अपने तिब्बती पड़ोसियों के संकट से आंखें मूंदे हुए है।

रेडियो फ्री–एशिया के तिब्बत प्रसारण धन में कटौती पर चिंता

ऐसे समय में जबकि बुश प्रशासन दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिये युद्ध लड़ रहा है व्हाइट हाऊस द्वारा नियुक्त ब्राडकास्टिंग बोर्ड आफ गवर्नर्स ने तिब्बती प्रसारणों के लिये दिये जाने वाले धन में 20 प्रतिशत से अधिक कटौती करने का फैसला किया है। इसके अलावा इन प्रसारणों के समय में भी 50 प्रतिशत तक की कटौती की जायेगी।

इस फैसले से चिंतित लोगों का कहना है कि बोर्ड के इस फैसले का मतलब यह हुआ कि तिब्बतियों को समाचार आदि के लिये सरकारी चीनी रेडियो के प्रोपेगेंडा पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा।

यह बोर्ड रेडियो फ्री एशिया (आरएफए) एवं वायस आफ अमेरिका (वीओए) पर नियंत्रण करता है। बोर्ड ने हाल ही में आरएफए एवं वीओए द्वारा तिब्बती प्रसारण के लिये दिये जाने वाले धन को घटाने का फैसला किया जो पहले 75 लाख डालर था। ग्रांट में यह कटौती वित्त वर्ष 2008 के बजट पैकेज का हिस्सा है जिसे व्हाइट हाऊस ने कांग्रेस के पास भेजा है।

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो तिब्बती सेवा के प्रसारण घंटों में लगभग आधी कटौती हो जायेगी। दलाई लामा फाउंडेषन के अध्यक्ष तेनज़िन टेथोंग ने डेली वैरायटी से कहा, ''अगर धन में कटौती की जाती है तो तिब्बत में रह रहे अनके लोगों के लिये सरकारी चीनी प्रसारणों के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा।''

रूसी मीडिया में दलाई लामा तथा तिब्बत के बारे में व्यापक कवरेज

रूसी जनता में दलाई लामा के प्रति समर्थन बढ़ा

मास्को, (तिब्बेतनेटडाटकाम) रूस के मीडिया ने तिब्बत के बारे में व्यापक जानकारी का प्रकाशन एवं प्रसारण किया है जिनमें तिब्बत की मौजूदा स्थिति, चीन के साथ मौजूदा वार्ता एवं आज की दुनिया में शांति की स्थापना में दलाई लामा की भूमिका जैसे मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

उल्लेखनीय है कि कालमिकिया गणतंत्र ने अपने देश का शीर्ष नागरिक सम्मान 'द व्हाइट लोट्स ' हाल ही में दलाई लामा को प्रदान किया था। यह अवार्ड देने के समारोह के लिये रूसी मीडिया का एक बड़ा दल धर्मशाला गया था।

रूस के रेन–टीवी ने 24 दिसंबर 2006 को दलाई लामा के साथ एक विस्तृत साक्षात्कार भी प्रसारित किया था। इसमें तिब्बत, चीन, वैश्विक राजनीति, सामाजिक एवं पर्यावरण समस्याओं जैसे अनेक मुद्दों पर विस्तार से बात की गई।

इसी तरह 28 दिसंबर 2006 और एक जनवरी 2007 को रूस के लोकप्रिय रेडियो स्टेशन 'इको मोस्कवी' ने दलाई लामा का विस्तृत साक्षात्कार प्रसारित किया। यह साक्षात्कार 48 मिनट का था और इस दौरान एक परिचर्चा भी प्रसारित की गई जिसमें तीन पत्रकार शामिल हुए। इनमें से एक पत्रकार हाल ही में धर्मशाल की यात्रा पर आये थे।

इस कार्यक्रम में दलाई लामा के बारे में रूस के आम लोगों के विचारों को भी प्रसारित किया गया। इन विचारों से स्पष्ट हो रहा था कि दलाई लामा के बारे में रूसी जनता के मन में कितना आदर है। जिन 300 लोगों के विचार इस दौरान लिये गये उनमें से 84.4 प्रतिशत ने यह इच्छा जताई कि दलाई लामा को रूसी संघ का अध्यक्ष बनाकर भी उन्हें खुशी होगी। तीन एवं पांच जनवरी को रूसी टेलीविजन चैनल टीवीसी ने दलाई लामा का विस्तृत साक्षात्कार प्रसारित किया। कालमीकिया में स्थानीय मीडिया ने तिब्बत, इसकी संस्कृति, अध्यात्म तथा तिब्बत एवं कालमीकिया के संबंधों पर व्यापक सामग्री प्रकाशित की।

ऐसा अनुमान है कि हजारों रूसी भाषी लोगों ने इन कार्यक्रमों को देखा सुना क्योंकि ये सभी टेलीविजन एवं रेडियो चैनल काफी लोकप्रिय माने जाते हैं।

इस कार्यक्रम में दलाई लामा के बारे में रूस के आम लोगों के विचारों को भी प्रसारित किया गया। इन विचारों से स्पष्ट हो रहा था कि दलाई लामा के बारे में रूसी जनता के मन में कितना आदर है। जिन 300 लोगों के विचार इस दौरान लिये गये उनमें से 84.4 प्रतिशत ने यह इच्छा जताई कि दलाई लामा को रूसी संघ का अध्यक्ष बनाकर भी उन्हें खुशी होगी।

तिब्बत में चीनी रेलगाड़ी के खिलाफ पर्यटकों का बीजिंग में प्रदर्शन : लूट के खिलाफ

चीनी रेल योजना तिब्बत को लूटने के लिये

तिब्बत पठार में 600 नये खनिज भंडारों का पता चला

''रेल लाइन को खनिज भंडारों वाले क्षेत्र से लेकर जाना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि चीन की इस रेल लाइन से तिब्बतियों का भला करने की मंशा कभी नहीं रही बल्कि इसका उद्देश्य तो तिब्बत की प्राकृतिक संपदा को लूटना और चीन की खनिज आयात पर निर्भरता को कम करना था।

चिंघाई (आम्दो प्रांत) चीन के भू सर्वेक्षकों को अचानक ही अधिगृहीत तिब्बत में मूल्यवान एवं विशाल खनिज भंडार मिलने लगे हैं। रोचक बात तो यह है कि हाल ही के महीनों में की गई इस तरह की घोषणाओं के अनुसार इस तरह के लगभग सभी भंडार चीन द्वारा तिब्बत में नवनिर्मित रेल परियोजना के आस पास के क्षेत्रों में ही पाये गये हैं।

अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इन घोषणाओं से चीन की इस महंगी रेल परियोजना के असली मकसद सामने आने लगे हैं। चीन द्वारा तिब्बत में रेल परियोजना की लागत पांच अरब अमेरिकी डालर से ज्यादा रही और यह तिब्बत में गत 50 साल की सबसे महंगी परियोजना है।

चाइना ज्योलाजिक्ल सर्वे ने 12 फरवरी को तिब्बत पठार में 600 नये खनिज भंडारों का पता लगने की घोषणा की। इन खनिज भंडारों में अधिकतर स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र, सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) और चिंघाई (तिब्बत का आम्दो प्रांत जिसे तिब्बत से अलग कर दिया गया है) में हैं और इनमें लौह, जस्ता, सीसा एवं तांबे के भंडार हैं।

चीन के ज्योजाजिक्ल सर्वे को अपने सात वर्षीय क्षेत्रीय सर्वेक्षण के तहत अब तक तिब्बत के पठार पर लगभग 5,000 खनिज भंडार मिल चुके हैं। आरंभिक अनुमानों के अनुसार तांबे के भंडारों से तीन करोड़ टन तांबा, जस्ते के भंडारों से चार करोड़ टन जस्ता तथा लौह अयस्क भंडारों से एक अरब टन लोहा धातु हासिल की जा सकती है। तिब्बत के इस पठार में क्रोमियम, सोने, चांदी एवं कोबाल्ट आदि के भी भंडार मौजूद हैं।

चुआलोंग (तिब्बत) में मिले एक तांबे के भंडार की अनुमानित क्षमता तो 78.9 करोड़ टन आंकी गई है और यह चीन एवं तिब्बत में अपनी तरह का सबसे बड़ा भंडार है। तिब्बत में खनिज भंडार मिलने संबंधी इन समाचारों ने तिब्बतियों के इस संदेह की पुष्टि कर दी है कि चीन की मंशा नयी रेल लाईन का इस्तेमाल तिब्बत के विशाल खनिज भंडारों को लूटने में करने की है। चीन ने अपने पहले के सरकारी बयानों में कहा था कि रेल लाइन का उद्देश्य तिब्बत में विकास करना है।

चीन की खनिज कंपनियां तिब्बत की विशाल खनिज संपदा को तिब्बत से बाहर ले जा सकेंगी पर इसका कोई लाभ तिब्बतियों को नहीं मिलेगा। फ्री टिबेट कैंपेन (एफटीसी) के मट्ट व्हिटीकेस ने कहा, ''अधिगृहित तिब्बत में चीन की खनन गतिविधियां दिन दहाड़े लूट है।''

उन्होंने कहा, ''रेल लाइन को खनिज भंडारों वाले क्षेत्र से लेकर जाना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि चीन की इस रेल लाइन से तिब्बतियों का भला करने की मंशा कभी नहीं रही बल्कि इसका उद्देश्य तो तिब्बत की प्राकृतिक संपदा को लूटना और चीन की खनिज आयात पर निर्भरता को कम करना था।''

उन्होंने कहा कि तिब्बत पठार में चीन की खनन गतिविधियों को तिब्बतियों ने अपनी स्वतंत्र एवं पूर्व सहमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों को इस बात का फैसला करने की आजादी मिलने तक कि उनके आर्थिक संसाधनों का किस तरह इस्तेमाल किया जाये, पश्चिमी देशों की खनिज कंपनियों को चीनी कंपनियों के साथ इस बारे में गठजोड़ स्थापित करने से बचना चाहिए।

तिब्बत में और बाहर रहने वाले तिब्बतियों का मानना है कि रेल सेवा के चलते लाखों हान चीनी तिब्बत में आयेंगे और तिब्बती अपनी मातृभूमि में ही अर्थहीन अल्पसंख्यक बन कर सिकुड़ने लगेंगे। इसी तरह इस लाइन से चीन द्वारा तिब्बत के सैन्यीकरण को भी गति मिलेगी। रेल लाइन के चलते चीन अपने सैनिकों को रसद एवं सैन्य साजो सामान की सतत एवं तीव्र आपूर्ति कर सकेगा।

लेकिन चीनी 'विषेषज्ञों' का कहना है कि रेलवे के इस्तेमाल से क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं 'देश' (चीन) की संसाधनों की मांग की आपूर्ति होगी।